

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com



पत्रांक : ०५

दिनांक 1-2-2010

प्रेस विज्ञप्ति

अध्यक्ष

अरूण चन्द्र मिश्र

(M) 9835281295

(M) 9939469410

(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष

* शम्भु नाथ मिश्र

(M) 9431619672

(O) 9334387630

(F) 0612-2504498

(R) 0612-2288139

* अख्ताक अहमद

(M) 9934280177

(O) 0612-2219693

महासचिव

सुशील कुमार

(M) 9431091417

(O) 9431818484

संयुक्त सचिव

* राजयनन्द खडियार

(M) 9431093157

(O) 9431818010

* अनिल कुमार

(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष

चन्द्र शेखर सिंह

(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष

सोमेश बहादुर माथुर

(M) 9431407901

(O) 9334387555

राज्य सरकार के द्वारा राज्य के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन का पुनरीक्षण मंत्रिपरिषद के दिनांक 29-12-09 को हुई बैठक से अनुमोदन प्राप्त कर संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21-01-2010 के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

आज बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों के द्वारा निर्गत संकल्प की गहन रूप से समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि वित्त विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक 29-12-2009 की बैठक में जिस प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त किया गया है, उसमें अनुलग्नक 5 का अनुमोदन लिया गया था जिसमें 5 पृष्ठ ही रखे गये थे, जबकि निर्गत संकल्प में पदों की सूची 92 पृष्ठों का है।

इसी प्रकार संलेख में प्रीमियर सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों के लिए जिस वेतनमान की स्वीकृति प्राप्त की गयी है, उसे निर्गत संकल्प में दर्शित नहीं किया गया है। वित्त विभाग द्वारा निर्गत संकल्प ज्ञापांक 630 दिनांक 21.01.10 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा को 8000 से 13500 के बदले जानबूझ कर 6500-10,500/- देकर पे बैंड-II में ग्रेड पे 5400 दे दिया गया है।

वित्त विभाग के द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत संलेख से हटकर संकल्प निर्गत कर गुमराह करने की कोशिश की गयी है जिसे बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भर्त्सना करती है। बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को 13-1-2009 को मंत्रिपरिषद की बैठक में 8000-13500 /- का परिवर्तित पे बैंड-III में ग्रेड पे 5400 रूपया दिया गया है, उसमें वित्त विभाग द्वारा परिवर्तित करने से बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं।

संघ के सदस्यों के आक्रोशित भावना एवं आन्दोलनात्मक कार्रवाई करने के लिए उतारू रूख पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अध्यक्ष के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि चूंकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से प्रीमियर सेवा के पदाधिकारियों के वेतनमान के संबंध में पुर्नावलोकन करने का आश्वासन दिया है, ऐसी परिस्थिति में तत्काल इस विसंगति एवं मंत्रिपरिषद तथा सरकार को गुमराह करने की कार्रवाई पर मुख्य सचिव महोदय के ध्यान में लाया जाय। साथ ही सरकार से यह अनुरोध किया जाय कि वैसे पदाधिकारी जो जानबूझ कर कार्य संस्कृति के सौहार्दपूर्ण वातावरण को क्षत-विक्षत करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें शिनाख्त कर अन्य वरीय पदाधिकारियों से इसकी जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय।

(ए० सी० मिश्र)

अध्यक्ष

ज्ञापांक ०५ पटना, दिनांक 1-2-2010

प्रतिलिपि:- सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों हिन्दी/अंग्रेजी को प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित।

(ए० सी० मिश्र)

अध्यक्ष